ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-7* October-2021
Anthology : The Research

आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक शासन अव्यवस्था
Modern Indian Democratic Governance Disorder

Paper Submission: 15/10/2021, Date of Acceptance: 23/10/2021, Date of Publication: 24/10//2021

वासुदेव चावला
पूर्व सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय लोहिया
महाविद्यालय, चूरू,
राजस्थान, भारत

सारांश

आधुनिक युग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का युग है। लोकतंत्र में राज्य का ढांचा ही लोकतांत्रिक होना पर्याप्त नहीं है, अपितु प्रशासन भी लोकतांत्रिक होना चाहिये। भ्रष्टाचार भारतीय समाज की सर्वकालिक तथा सर्वव्यापी समस्या है। प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य ने अपने ग्रन्थ ''राजनीतिक अर्थशास्त्र में लिखा है कि ''जिस प्रकार जिह्वा पर रखे हुए शहद का स्वाद न लेना असम्भव है उसी प्रकार शासकीय अधिकारी के लिये राज्य के राजस्व के एक अंश का भक्षण न करना असम्भव है'' कौटिल्य का यह कथन इस ओर इंगित करता है कि भ्रष्टाचार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप मे रहा है।धर्म, ज्ञान, कला, संस्कृति, उच्चतम् मानवीय मूल्यों के साथ-साथ हमारे देश में भ्रष्टाचार की भी परम्परा देखी जा सकती है। भगवतद्गीता के अध्याय तृतीयके श्लोक 21, में भ्रष्टाचार के प्रवाह का संकेत मिलता है। मनु ने भी 1000 ई.पू. उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर पाबंदी लगाने तथा उनकी सम्पत्ति जब्त करने का आदेश दिया था जो ग्रामीणों से घूस लेते हों।

The modern era is the era of democratic governance systems. In a democracy, the structure of the state itself is not enough to be democratic, but the administration should also be democratic. Corruption is an all-time and ubiquitous problem of Indian society. The famous scholar Kautilya has written in his book "Political Arthashastra" that it is impossible not to taste the honey kept on the tongue.

Similarly, it is impossible for a government official not to consume a part of the state's revenue." This statement of Kautilya indicates that corruption has been in the Indian political system in one form or the other since ancient times. Religion, Knowledge Along with art, culture, highest human values, the tradition of corruption can also be seen in our country.

The flow of corruption is indicated in verse 21 of Chapter III of the Bhagavad Gita. Manu also wrote in 1000 BC. Order was given to ban those corrupt officials and to confiscate their property who take bribe from the villagers.

मुख्य शब्दः भारतीय राजनीतिक,लोकतांत्रिक शासन, भ्रष्टाचार, मानवीय मूल्य ।

Indian Political, Democratic Governance, Corruption, Human Values.

प्रस्तावना

मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के प्रथम 34 श्लोक भ्रष्ट आचरण का उल्लेख करते हुए उन्हें न अपनाने का उपदेश देते हैं। इसी प्रकार अष्टम अध्याय में राजा को 18 व्यवहारों से बचने की सलाह दी गई है। ये सभी 18 व्यवहार भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। एक अन्य स्थान पर मनु स्पष्टतः कहते हें कि 'राजा अथवा राजा का प्रतिनिधि दूसरों से धन प्राप्ति की इच्छा में न तो कोई वाद (प्रकरण) उत्पन्न करे और न ही वाद को निरस्त (खारिज) करें।' उज्जयिनी के शासक तथा बाद में योगी बने भर्तृहरि ने अपने नीतिग्रंथ 'नीतिशतक' में तीन प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है- अधम, मध्यम तथा उत्तम। यहाँ अधम व्यक्ति को भ्रष्ट आचरणकरने वाला बताया गया है। योग महर्षि पतंजलि ने यम नियम की व्याख्या करते हुए नैतिक आचरण पर बल दिया है।इसी तरह अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में निःसंदेह एक सुनियोजित नौकरशाही व्यवस्था का विकास हुआ लेकिन ब्रिटिश धनलोलुपता ने तत्कालीन दौर में भ्रष्टाचार में असीम वृद्धि की। आजादी के दौरान यही भ्रष्टाचार हमें विरासत में प्राप्त हुआ, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।सदियों से चली आ रही इस परम्परा का स्वरूप अब विशाल हो गया है । जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा वाले इस प्रजातंत्र देश में भ्रष्टाचार इतना घुल मिल गया है कि राजनीतिक, प्रशासकीय, न्यायिक और पुलिस विभागों, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, शिक्षा, कला, मनोरंजन, सेना, जीवन के हर पहलू भ्रष्टाचार से सराबोर है। रिश्वत लेना और देना जैसे स्वीकृत कार्य विधि बन गई है। ''भ्रष्टाचार'' जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, वह तत्व जो कि आचरण को भ्रष्ट करता है। भ्रष्टाचार उन शब्दों में से एक है जिसके श्रृव्य मात्र से हृदय घृणा भाव से उद्वेलित हो उठता है। जब मानव चरित्र नैतिकता और सत्य के अभाव में आचरण करता है और पूर्णतः तृष्णा से ग्रसित होकर व्यक्तिगत् लाभ हेतु प्रत्येक कार्य करता है तब इसे ही हम भ्रष्ट आचरण कहते हैं।

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ भ्रष्ट अथवा बिगड़े हुए आचरणसे लिया जाता है। सरल शब्दों में भ्रष्टाचार को ''रिश्वत का कार्य'' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे ''निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिसमें कानून तोड़ना शामिल हो या जिससे समाज के मानदण्डों का विचलन

हुआ हो'' भी कहा जाता है। विद्वान डी.एच. वेली ने भ्रष्टाचार को इस प्रकार बताया है कि ''निजी लाभ के विचार के परिणामस्वरूप सŸाा का दुरूपयोग जो धन सम्बंधित नहीं भी हो सकता है।'' विद्वान एन्ड्रिस्क् ने कहा है कि ''ऐसे तरीकों में सार्वजनिक शक्ति का निजी लाभ के लिए प्रयोग जो कानून का उल्लंघन करता हो''। जे. नाय का कहना है कि ''भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिए सार्वजनिक पद का दुरूपयोग दर्शाता है''।

इलियट और मेरिल के अनुसार ''अपने अथवा अपने सगे-सम्बन्धियों, परिवार वालों और मित्रों के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई आर्थिक अथवा कोई अन्य लाभ उठाना भ्रष्टाचार है।'' इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार की परिभाषा करते हुए लिखा है ''राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ करने के लिये किसी निर्दिष्ट कत्र्तव्य का जान-बूझकर पालन न करना है''। राबर्ट ब्रुक्स के अनुसार ''इसमें किसी मूर्त या अमूर्त लाभ के लिये किये जाने वाले कानूनी कार्य भी सम्मिलित होते हैं''। बर्क के अनुसार ''भ्रष्टाचार सभी किस्म की अव्यवस्था का स्त्रोत है, यह हमारे संविधान, हमारे विवेक और हमारी आत्मा को क्षति पहुँचाता है''। मैरिस सैफेल के अनुसार ''भ्रष्टाचार वह व्यवहार है जो मानदंड़ों और सार्वजनिक भूमिका निर्वाह के कत्र्तव्यों को संचालित करने या निजी लाभों के लिए पदों के उचित उपयोग से विचलित होता है''। यह निजी लाभ कुछ कार्यों पर लगे प्रतिबंधों की अवहेलना करके या उस कार्य के प्रति कुछ कत्र्तव्यों को पूरा करने के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

विधि के अनुसार भ्रष्टाचार को परिभाषित करते हुए आई.पी.सी. की धारा 161 में कहा गया है कि ''जो व्यक्ति शासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने अन्य किसी व्यक्ति के लिए विविध पारिश्रमिक से अधिक कुछ घूंस लेता है या स्वीकार करता है अथवा लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है या किसी कार्य को करने या न करने के लिए उपहार स्वरूप या अपने शासकीय कार्य को करने में किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास, केन्द्रीय या अन्य राज्य सरकार या संसद या विधानमंडल या किसी लोकसेवक के संदर्भ में करता है''।भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1962 का अभिमत है ''शब्द के व्यापक अर्थ में एक सार्वजनिक पद अथवा जन-जीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थपूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है''। समिति के अनुसार स्वयं या परिवार, सम्बन्धियों या मित्रों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी प्रकार का आर्थिक या अन्य भौतिक रूप लाभ प्राप्त करना हो तो भ्रष्टाचार एक अत्यन्त साधारण तरीका है, जबकि आधुनिक समाज में नित्य-प्रति बढती हुई विषमताओं में बुराई के भिन्न-भिन्न नए स्वरूप प्रकट होते जा रहे है।जार्ज बर्नार्डशॉ ने ठीक ही लिखा है ''राजनीति दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों के लिए अन्तिम शरणालय है''। अतः हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा स्वीकृत आचार - संहिता की अवहेलना करके दूसरों को कष्ट पहुँचाकर निजी स्वार्थो व इच्छओं की पूर्ति करना की भ्रष्टाचार है। स्वार्थ और लोभ के कारण किया गया मानवीय व्यवहार भ्रष्टाचार के अन्तर्गत आता है। भ्रष्टाचार का दायरा बहुत बड़ा है। ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वत्र पसरा है। ''केन्द्रीय सतर्कता आयोग'' ने भ्रष्टाचार के 27 प्रकारों का उल्लेख किया है। एक अनुमान के अनुसार सरकार का एक वर्ष का जितना बजट होता है देश में उससे अधिक कालाधन है। काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था के आगे वैष्वीकरण के ''युग'' में उदारीकृत अर्थव्यवस्था की नई चुनौतियों का सामना करने में राष्ट्र को अनेक कठिनाईयों का अनुभव हो रहा है।

प्रस्तावित शोध अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह ज्ञात हो सके कि राजनैतिक भ्रष्टाचार का देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 9.5 की दर से बढ़ रहा है, परंतु वित्त मंत्रालय का एक आकलन है कि यदि देश के काले धन को विकास प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाये तो जीडीपी में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है और भारत 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। आज भ्रष्टाचार को आम व्यक्ति ने अपनी नियति मान लिया है। हम निराशावादी और नकारात्मक सोच का परित्याग करें और जहाँ कहीं हमें यह लगे कि गलत हो रहा है तब हम सक्रिय रूप से उसका विरोध करें। आज हमें एक सक्रिय और जिम्मेदार नौकरशाही की जरूरत है। एक प्रजातांत्रिक लोक कल्याणकारी राज्य के प्रशासन में अखंडता, निष्कपटता और स्पष्टवाद की विशेष जरूरत होती है। अब सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर और सूचना प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है। शिक्षा के प्रसार ने भी जन जागरूकता को बढ़ाया है। उम्मीद है कि पूरी तरह नहीं तो कुछ हद तक इस पर अवश्य ही पाबंदी लगेगी।

अब तक किये गये कार्यों की समीक्षा

सी.पी. श्रीवास्तव (2001) ने अपनी पुस्तक 'Corruption : India"s Enemy within' में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार के बढ़ते प्रभाव को दर्षाया है। भ्रष्टाचार ने अपनी जड़े इतनी मजबूत कर ली है कि आम आदमी इससे कुंठित होता जा रहा है, इसका वर्णन किया है। अजीत मिश्रा (2005) की पुस्तक The Economic of Corruption में भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं पर 15 अध्याय है। यह पुस्तक भ्रष्टाचार की अवधारणा, इतिहास मूल्यांकन, इसके अस्तित्व, कारण,

परिणाम तथा भ्रष्टाचार से संघर्ष पर प्रकाष डालती है। इस पुस्तक में प्राथमिक रूप से भ्रष्टाचार के आर्थिक पहलू को दर्षाया गया है। एन. विट्टल (2003) ने अपनी पुस्तक Corruption in India द्वारा सरकार की भ्रष्टता को हास्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। लेखक का मानना है कि भ्रष्टाचार की गम्भीरता को राजनीतिक व्यवस्था द्वारा भूला दिया गया है, इस और सार्थक संघर्ष की आवष्यकता है।

एस.के. दास (2001) ने अपनी पुस्तक ‘‘Public office Private Interest : Bureaucracy and Corruption in India' में नौकरशाही के इतिहास, समस्या के कारण तथा संभव उपायों पर प्रकाशडाला है, एवं भ्रष्टाचार के कारण को रेखांकित किया है।

रॉबर्ट एन. जान्सन (2004) ने अपनी पुस्तक 'The Struggle against Corruption, A Comparative Study' में भ्रष्टाचार की परिभाषाा एवं नैतिक पहलूओं को बताया गया है। इसमें चार देशों में भ्रष्टाचार के विकास तथा रूस एवं भारत जैसे देषों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध बताने का प्रयास किया है। यह पुस्तक भ्रष्टाचार पर सार्वभौमिक संवाद कर, उससे संघर्ष का प्रयाय करती है।

सुशन रोज अकरमन् (1991)ने अपनी पुस्तक 'Corruption And Government : Courses, Consequences and Reform में भ्रष्टाचार का वैश्विक परिद्रश्य प्रस्तुत किया है। इसमें भ्रष्टाचार से हो रही हानियों पर प्रकाश डाला गया है जैसे असंतुलन, असमानता, सरकार की प्रभावहीनता, एवं वृद्धि-निवेश की सीमितता तथा आर्थिक एवं राजनीतिक ढाचे में परिवर्तन कर भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रेरित किया है।

सेलिक एस. हरिशन (1998) ने अपनी पुस्तक India and Pakistan : The first Fifty Years' में भारत और पाकिस्तान की स्वतन्त्रता के 50 वर्षों की प्रगति, समस्याएं, विदेष नीति, रक्षा नीति तथा यू.एन.ओ. से सम्बन्ध का वर्णन भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रस्तुत किया है।

माईकल जोन्सटन (2005) ने अपनी पुस्तक 'Syndromes of Corruption wealth, Power and Democracy' में भ्रष्टाचार के खतरे को बताते हुए इसके मुख्य लक्षणों, आर्थिक बाजार, अभिजन समाज, जनप्रतिनिधि, कार्यालयी कर्मचारी आदि पर प्रकाष डाला है तथा लक्षणांे के बढ़ने के कारण बताये हैं।

सुनील खिलानी (1999) ने अपनी पुस्तक 'The Idea of India' में कांग्रेस के एकाधिकार की समाप्ति क्षेत्रीय दलों में बढ़ोतरी, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों में कमी गरीबी शहरीकरण आदि के कारणों व प्रभावों का वर्णन करते हुये भारत की विभिन्नता में एकता को दर्षाया है तथा भारतीय इतिहास को सूक्ष्मतापूर्वक प्रकाषित किया है।

सुमीर लाल (2006) की पुस्तक 'Can Good Economic Ever be Good Politics Case Study of India"s Power Sector' में विकासषील देषों में राजनीतिक दलों की स्थिति, राजनीतिक जागरूकता की कमी, जातीय राजनीति - परिणाम, प्रभाव व अनौपचारिक सम्बन्ध नेताओं के व्यवहार का गहनता से अध्ययन किया गया है तथा इसमें सुधारों का प्रयास किया है।

पैनी ग्रीन ;2001द्ध ने अपनी पुस्तक 'Sate Crime : Government, Violence and Corruption’ में राज्य के अपराधों, लक्षणों, क्षेत्रों का अध्ययन किया है यथाः राज्य विद्रोह, भ्रष्टाचार, निगम अपराध, अपराधिक नीतियों, गैर-कानूनी कार्यों का वर्णन करते हुए राज्य अपराध पर कहानियां, मुद्दे, वाद-विवाद है जिनमें मानवीय अधिकार, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राज्य की सीमाओं का अध्ययन किया गया है। इस पुस्तक में जो भी खोज की गई है वो अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के मामलों का अध्ययन कर समस्त सूचनाएं प्रदान करती है।

योगेन्द्र के. मल्लिक, चाल्स एच. केनडी, रोबर्ट सी. आबसर्ट (2001) ने अपनी पुस्तक 'Government and Politics in South Asia' में तुलनात्मक राजनीति के नये सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है जिसमें राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण, सरकार की कार्यविधि एवं परिणामों का वर्णन किया है।

सन्जा के.आई. (2005) ने अपनी पुस्तक 'Fallen Blue Knights : Controlling Police Corruption' में भ्रष्टाचार पर गहराई से अध्ययन किया है तथा न्यायालय, स्वतन्त्र आयोग व मिडिया की भूमिका का भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विकासात्मक ढंाचे का वर्णन प्रस्तुत किया है।

मनोरंजन मोहन्ती (एडिटर) (2004) ने अपने इस विवरण 'Class, Caste, Gender' में राजनीतिक प्रक्रियाओं में वर्ग, जाति, लिंग जैसे जटिल मुद्दों का वर्णन किया है जो सामाजिक असमानता को बढ़ावा देते हैं । पांच भागों में विभक्त यह पुस्तक भारतीय प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयत्न करती है।

घनश्याम शाह (एडिटर) (2002) ने 'Social movement and the state' के इस भाग में समूह, वर्ग, राज्य, सामाजिक गतिविधियों की उत्पति, जातीय एकता, निम्न वर्ग, महिलाओं, राज्य की परिस्थिति एवं धार्मिक तथ्यों का विस्तार से अध्ययन प्रस्तुत किया है।

राजीव देसाई (1999) ने अपनी पुस्तक 'Indian Business Culture' में भारतीय व्यापार का वर्णन करते हुए सांस्कृतिक मुद्दों विभिन्न कम्पनियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, बढ़ते निवेष व बढ़ते हुए व्यापार पर प्रकाष डाला गया है।

जिम मसौल्स (2002) ने अपनी पुस्तक 'Indian Nationalism : A History' में 19वीं व 20वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर प्रकाष डालते हुए राजनीतिक समूह, कांग्रेस, गांधी का नेतृत्व, अहिसांत्मक आन्दोलन का वर्णन प्रस्तुत किया है । आधुनिक भारत का वर्णन करते हुए नेतृत्व परिवर्तन एवं लोकतांन्त्रिक चेतना का महत्व प्रस्तुत किया है।

जॉन ए.जे. (2004) ने अपनी पुस्तक 'Brotherhood of Corruption : A Cop Breaks the Silence on Police Abuse, Brutality and Racial Profiling' में पुलिस की भ्रष्टता का वर्णन करते हुए उनकी भ्रष्ट कार्यविधि को दर्षाया है। पुलिस शक्ति का दुरूपयोग, महिलाओं से दुव्र्यवहार, फौजदारी मुकदमें, गिरफ्तारी आदि तकनीकों का प्रयोग किस तरह करती है को सविस्तार वर्णन प्रस्तुत किया है।

भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव

भ्रष्टाचार केवल सुशासन की गुणवत्ता को ही नुकसान नहीं पहुँचाता है बल्कि यह लोकतन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तों के लिए खतरा पैदा करता है। कुछ व्यक्तियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने से अन्य सामान्य व्यक्तियों के लिए अवसरों की ही कटौती ही नहीं होती है बल्कि संविधान की इस भावना को भी ठेस लगती है जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को आत्म सम्मान एवं समानता के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। भ्रष्टाचार मानव सम्मान एवं राजनीतिक समानता दोनों के आधारभूत मूल्यों को नष्ट करता है।आज समाज व राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार के संक्रमण से कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित है। धर्म, शिक्षा, संस्कृति, राजनीति, कला, मनोरंजन और खेलकूद आदि अनेक क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार ने अपने पाँव फैला लिए हैं। भ्रष्टाचार जीवन का अभिन्न अंग बन गया है तथा राष्ट्रीय संस्कृति के रूप में अपने चरित्र का विकास कर रहा है। बहुत से लोग नैतिकता के धरातल पर इसका औचित्य भी सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। तथाकथित बुद्धिजिवी, शिक्षित व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, प्रशासक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार पर बहस एवं व्याख्यान तो देते है, किंतु उसे अपनी नियति मानकर स्वयं उसका एक हिस्सा बनते जा रहे हैं इस मनौवैज्ञानिक उदासीनता ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के रूप में आज सामाजिक विकास की प्रक्रिया अवरूद्ध सी हो गई है प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सी गई है दोषी, निर्दोष सिद्ध हो रहे है और निर्दोष व लाचार व्यक्ति अकारण जेल में सजा काट रहे है। गरीबों के पेट की रोटी अमीर लोगों के हाथों छीनी जा रही है। धनबल एवं बाहुबल का बोलबाला यत्र तत्र सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है, पूर्व के वर्षों में वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप हुई हरित, श्वेत, नील, औद्योगिक एवं सूचना क्रांतियों के बावजूद भी वास्तविकता के धरातल पर सामाजिक विकास की स्थिति संतोषजनक नहीं है। समाज के अन्तिम छोर पर खड़े लाचार व्यक्ति के लिये जीवन की मौलिक आवश्यकताओं शुद्ध जल, शिक्षा, भोजन, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छ आवास उपलब्ध करा पाना सत्ता और सरकार के लिए टेडी खीर हो गया है। जनता के द्वारा, जनता के लिये, जनता की सरकार, जनता की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ सी हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. आधुनिक भारतीय लोकतंत्र शासन व्यवस्था में बदलते आयामों का अध्ययन करना।
2. लोकतान्त्रिक व्यवस्था में फ़ैल रहे भ्रष्टाचार का आकलन करना।
3. लोकतान्त्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए ठोस उपाय सूझना।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय शासन एवं राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार तभी नियंत्रित हो सकता है, जब राज्य एवं उसके उपकरणों को प्रभावी बनाया जाए। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए समितियों एव संस्तुतियों से काम नहीं चलेगा वरन् उच्च पदस्थ लोगों से लेकर नीचे तक के लोग अपने अधिकारों के साथ कत्र्तव्यों का भी समुचित रूप से निर्वाह करें। जब तक शीर्ष नेतृत्व इस दिशा में पहल नहीं करेगा भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया जा सकता। व्यक्तिगत अभिलाषाओं एवं सामाजिक आवश्यकताओं के बीच प्रभावकारी संतुलन पैदा करने के निमित्त राजनीति में शुचिता का जब तक पालन नहीं होगा, भ्रष्टाचार भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करता रहेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *एन्टोनी वी. बाउजा "पुलिस अनबाउन्ड: करप्षन ऐब्यूज, ऐन्ड हिरोइज्म बाई दा बॉयज् इन ब्लू, मैथ्युज बुक्स, पेरामाउन्ट प्रेस, न्यू योर्क, 2001*
2. *एन्टोनीयो, जुआन जे. ब्रदरहुड ऑफ करप्शन: ए कोप ब्रेकस दा साइलेन्स आॅन पुलिस ऐब्यूज, ब्युरटेलीटि, एन्ड रेशिएल प्रोफाइलिंग, षिकागो, 2004*
3. *बेट्स क्रिस्पन, बासु शुभोरिथिंकिंग इण्डीयन पोलिटिक्ल इंस्टीट्यूषनस, एन्थम प्रेस,लन्दन 2005*
4. *दास, एस.के. पब्लिक ऑफिस प्राइवेट इन्टरेस्ट, ब्यूरोक्रेसी एंड करप्षन इन इण्डिया, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यु.एस.ए. 2001*

5. दास, एच.एन. पॉलिटिकल सिस्टम आॅफ इंडिया, अनमोल पब्लिकेषन (प्रा.) लिमिटेड, नई दिल्ली, 1998
6. देसाई, राजीव इण्डियन बिजनसस कल्चर, बटरवर्थ, हॅनमेन 1999
7. डिसुजा, पीटर रोनाल्ड एवं ई श्रीधरन इण्डियाज पोलिटिक्ल पार्टीज सेज पब्लिकेषनस, नई दिल्ली 2006
8. गुप्ता, के.एन. करप्षन इन इण्डिया, अनमोल पब्लिकेषन, दिल्ली 2003
9. गुप्तू, नन्दनी द पोलिटिक्स आॅफ द अरबन पुअर इन अर्ली टवंटिथ सेचुरी इन्डिया, केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी प्रेस, यु.के. 2001
10. ग्रीन, पेनी एवं टोनी वार्ड स्टेट क्राइमः गर्वनमेन्ट, वोइलेन्स एन्ड करप्षन, प्लूटो प्रेस, लन्दन, यू.के. 2004
11. ग्रोवर, वीरेन्द्र इण्डियन गर्वनमेन्ट एन्ड पोलिटिक्स एट क्रोस रोड्सः पौलिटिक्ल इन्सटेबिलीटी, मनी पावर एन्ड करप्षन, पंजाब एन्ड कष्मीर प्रोब्लमज, सेक्यूलेरिज्म, रिलीजन एन्ड पोलिटिक्स, डवलपमेन्ट टुआर्डस 2000 ए.डी., दीप एन्ड दीप, दिल्ली 1995.
12. हॅस्टर, जे.टी. पोलिटिक्ल प्रिंसीपल्स एन्ड इण्डियन
13. सोवरनिटी, रूटलेज्, न्यूयार्क, 2001
14. आइकोविक, सन्जा के. फालन ब्लू नाइट्सः कन्ट्रोलिंग पुलिस करप्षन, आॅक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यु.एस.ए. 2005
15. जॉनसन, रोबर्ट एन. द स्ट्रगल अंगेस्ट करप्षनः ए कम्पेरेटीव स्टडी, पालग्रेव मेकमिलन, यु.एस.ए. 2004
16. जोषी, वसन्त सी. एवं
17. जोषी, विनय वि. मैनेजिंग इण्डियन बैंकस्ः द चैलेन्ज अहेड, सेज पब्लिकेषन्स, नई दिल्ली 2002
18. जॉन्सटन, माइकल सिन्ड्रोमस् आॅफ करप्षनः वेल्थ पॉवर एंड डेमोक्रेसी, केम्ब्रीज यूनिवर्सिटी प्रेस, यु.के., 2005
19. कोन्कले मॉरिन राइटिंग इन्डियन नेषन्सः नाटिव इन्टलेक्च्यूल्य एन्ड दा पोलिटिक्स आॅफ हिस्टोरीग्राफी, द यूनिवर्सिटी आॅफ नोर्थ केरोलिना प्रेस, यु.एस.ए. 2007
20. लाल, सुमिर केन गुड, इकोनोमिकस एवर बी गुड पोलिटिक्स ? केस स्टडी आॅफ इंडियाज पावर सेक्टर, वल्ड बैंक पल्कैषन्स इंडिया 2006
21. मिश्रा, अजीत द इकोनोमिक्स आॅफ करप्षन आॅक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यु.एस.ए. 2005
22. मोहन्ती, मनोरंजन मैथ्यू, जार्ज, रिचर्ड बाम एवं मा. रोग ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया एन्ड चाइना, सेज पब्कैषन्स इंडिया, दिल्ली 2007
23. मलिक, के. योगेन्द्रा,
24. चाल्स एस. केनेडी,
25. ओबर्सट, सी रॉबर्ट, केरीग
26. बेक्सटर गर्वनमेन्ट एन्ड पोलिटिक्स इन साऊथ एषिया, वेस्टव्यू प्रेस, यु.के. 2001
27. मॉसल्स, जिम इंडियन नेसनलिजमः ए हिस्ट्री न्यूडॉन प्रेस, नई दिल्ली 2004
28. नन्दी, आषीष टाइम वार्पसः साइलन्ट एन्ड इवासिव पासट्स इन इण्डियन पोलिटिक्स एण्ड रिलीजन, रूटगर्स प्रेस, यु.एस.ए. 2002
29. श्रीवास्तव, सी.पी. करप्षनः इण्डियाज एनिमी विदित, मैकमिलन, दिल्ली 2001
30. सिडनी, लॅमन बी.यस्टरडे एण्ड टुडे इन इण्डिया, एलन एन्ड कम्पनी, लन्दन, यु.के., 2001
31. सिन्हा, असीमा द रीजनल रूटस आॅफ डवलपमेन्टल पोलिटिक्स इन इन्डियाः ए डीवाइडेड लेवियाथन, इन्डियाना यूनिवर्सिटी प्रेस, यु.एस.ए. 2005
32. सिंह, निर्मल कुमार अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति, वाणी प्रकाषन, नई दिल्ली 2000
33. ठाकुर, उपेन्द्र करप्शन इन एनसियन्ट इण्डिया, अभिनव पब्लिकेषन्स, दिल्ली, इन्डिया 2003
34. विट्ठल, एन. करप्शनइन इंडिया, एकेडिमिक फाउन्डेषन, दिल्ली 2003